

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 3611
जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल बिक्री

3611. सुश्री एस. जोतिमणि:

श्री विनसेंट एच. पाला:

श्री टी.एन. प्रथापन:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री के. सुधाकरन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2014 से आज तक देश में ऑटोमोबाइल बिक्री की माह-वार संख्या क्या है;
- (ख) 2014 से आज तक देश में ऑटोमोबाइल बिक्री का माह-वार मूल्य क्या है;
- (ग) 2014 से आज तक बंद हुए ऑटोमोबाइल और अनुषंगी विनिर्माण इकाइयों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (घ) ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनः पूंजीकरण, भारत स्टेज VI में परिवर्तन, पुराने वाहनों को बंद करने की नीति, एम.एस.एम.ई हेतु बैंक ऋण की पुनर्गठन नीति, ह्यस और जी.एस.टी दरों में परिवर्तन पर विचार करेगी;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) 2015 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रोजगार सृजन और नई नौकरियों का ब्यौरा क्या है और इसका केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क)

सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री की संख्या (संख्या लाख में)						
माह	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अप्रैल	15.5	15.8	19.0	20.3	23.8	20.0
मई	16.9	16.8	18.5	20.4	22.8	20.9
जून	15.8	16.2	18.0	18.2	22.8	20.0
जुलाई	16.0	16.2	18.3	20.8	22.5	18.3

अगस्त	16.6	16.3	20.1	23.0	23.8	18.2
सितम्बर	18.9	18.8	22.6	24.9	25.8	20.0
अक्तुबर	17.9	20.4	22.0	21.6	24.9	21.8
नवम्बर	16.0	16.5	15.6	19.4	20.4	
दिसम्बर	15.1	15.0	12.2	16.7	16.2	
जनवरी	16.5	17.0	16.2	21.2	20.2	
फरवरी	15.3	17.0	17.2	21.1	20.3	
मार्च	16.8	18.6	18.8	22.2	19.1	

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वाहनों की घरेलू बिक्री का कारोबार निम्नानुसार है:

सभी श्रेणी के वाहनों की घरेलू बिक्री के माध्यम से कारोबार अनुमान (करोड़ में)		
2016-17	2017-18	2018-19
415,811	464,447	490,849

(ग): सरकार को किसी भी मोटर वाहन अथवा सहयोगी विनिर्माण इकाई को बंद किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) से (च): सरकार, जब कभी अपेक्षित होता है, उद्योग के व्यापक और निरंतर विकास के लिए अनेक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं इसमें सुधार करने का हमेशा प्रयास करती है।

सरकार, समय-समय पर आवश्यकताओं के विषयनिष्ठ आंकलन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में पूंजी निवेश करती है।

एमएसएमई के लिए बैंक ऋण के पुनर्गठन हेतु नीति के संबंध में, यह बताया जाता है कि आरबीआई ने माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों को अग्रिमों के पुनर्गठन हेतु एक नीति जारी की है।

(छ): विभाग के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।
